(c) if so, the the steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH): (a) It is not correct to say that the fertiliser policy as announced in December 1965 has not attracted foreign investors as seven proposals for foreign investment have been approved and are in various stages of implementation.

(b) and (c). Do not arise.

हरिजनों का कल्याण

2772. **श्री अ० सि० सहगल :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे कार्य-क्रमों के अन्तर्गत सरकार विभिन्न राज्यों को हरिजनों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिए किन आधारों पर वित्तीय सहायता देती है;

(ख) 1967–68 में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) 1968–69 में कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है और उपरोक्त सहायता के प्रत्यक मामले में क्या औचित्य है ?

समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डा० फूलरेणु गुह): (क) समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नियत की गई प्राथमिकता के आधार पर।

(ख) एक विवरण, जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन 1967-68 में वित्तीय सहायता की शिखरताएं दिखाई गई हैं। सभा पटल पर रखा जाता है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या [LT.333/68]

(ग) 1968–69 के लिए अन्तिम विनिधानों का निश्चय बजट प्राक्कलनों के, जो इस समय सदन के सामने हैं, आधार पर किया जाएगा। विनिधान साधारण तथा वार्षिक योजना विचार विमर्श पर तथा प्रत्येक राज्य द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित कार्य-क्रमों पर आधारित होते हैं।

मकानों के निर्माण के लिये भूमि का आवंटन

2773. **श्री जोगेश्वर यादव :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन किसानों तथा श्रमिकों द्वारा गांवों तथा शहरों में मकान बनाने हतु भूमि के आवंटन के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). यद्यपि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को गांवों और शहरों में मकान बनाने के लिए भूमि के नियतन की कोई अलग से योजना बनाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी अन्य बातों के साथ इस मन्त्रालय की ग्राम आवास परियोजना स्कीम में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को निःशुल्क मकानों के स्थान देने की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिये योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें अपने नियतन का एक तिहाई प्रयोग कर सकती है। इस कार्य-क्रम के लिए कुल व्यय की व्यवस्था भारत सरकार सीधे ही अनुदान के रूप में करती है। खेतीहर मजदूर किसी भी ग्रामीण की भांति अपने मकान बनाने के लिए इस योजना से ऋण पाने के पात्र हैं।

नासिक के सिक्योरिटी प्रेस मुद्रणालय से नोटों की चोरी

2774. **श्री बसवंत :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सिक्योरिटी प्रेस, नासिक से सौ रुपये वाले कुछ नोट चुरा लिए गए हैं;